

332

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

ग्वालियर/अनूपपुर/भू-रा/2018/0848

अशोक कुमार छिब्वर पिता केदारनाथ छिब्वर निवासी- ग्राम सकरिया तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.) --आवेदक

विरुद्ध

1. जगदीश प्रसाद,
2. चन्द्रिका प्रसाद, दोनो पुत्रगण गौरीशंकर केशवानी,
3. चन्द्रशेखर,
4. पंकज, दोनो पुत्रगण अनूपपुर चेतनानगर तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
5. सीताराम पटेल पुत्र स्व श्री रामदास पटेल, ग्राम सकरिया तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
6. पवन छिब्वर पुत्र केदारनाथ छिब्वर, निवासी- ग्राम सकरिया तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

विवाद लागू करार  
इस आज दि. 1-2-18  
प्रस्तुत प्रारंभिक तर्क हेतु  
दिनांक 16-2-18 नियत।

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर  
1-2-18

---अभावेदकगण

विवाद लागू करार  
हस्ताक्षर  
01-02-2018

न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील जिला अनूपपुर, द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ-12/16-17 में पारित आदेश पारित दिनांक 24/10/2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:

1. यहकि, आवेदक ने अपने भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की सर्वे क्रमांक 6 का सीमांकन अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा कराये जाने हेतु कलेक्टर

- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- दो/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2018/0848

अशोक कुमार छिब्बर विरुद्ध जगदीश प्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों की अभिभाषक हस्ताक्षर
18-03-2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</li><li>2. आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित ।</li><li>3. यह निगरानी तहसीलदार, तहसील अनूपपुर, जिला-अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24-10-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</li><li>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</li><li>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी, जिला-अनूपपुर को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 13-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</li></ol>	<p style="text-align: center;">(आर के जैन) सदस्य 18/03/19</p>